

संपादकीय

टीएमसी नेताओं की टिप्पणी निंदनीय

कोलकता में कानून की एक छात्रा से सामूहिक दुराचार के मामले में पश्चिम बंगाल में सतारूद पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं की अनर्गल टिप्पणी स्त्री की मर्यादा के खिलाफ शर्मनाक व संवेदनहीन प्रतिक्रिया है। एक बार फिर शर्मनाक ढंग से पीड़िता पर दोष मढ़ने की बेशर्म कोशिश की गई है। टीएमसी की महिला नेत्री महुआ मोड़ना ने पार्टी के नेताओं के बयान पर निराशा व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि इन राजनेताओं के बयान में स्त्री-द्वेष पार्टी लाइन से परे है। वहीं इससे भी बदतर स्थिति यह है कि जिस पार्टी के नेताओं ने ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए हैं, उस पार्टी की सुप्रीमो एक महिला ही हैं। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि ममता बनर्जी जैसी तेजतर्रार मुख्यमंत्री के शासन और नेतृत्व के वर्षों के दौरान टीएमसी के भीतर संवेदनशीलता लाने और मानसिकता में बदलाव लाने के प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। विडंबना यह है कि पीड़िता के प्रति निर्लज्ज बयानबाजी अकेले पश्चिम बंगाल का ही मामला नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी संवेदनहीन टिप्पणियां सामने आती रही हैं। देश के विभिन्न राज्यों में कई जघम्य अपराधों के बाद टिप्पणियों में पितृसत्तात्मक रीति-रिवाजों को ही उजागर किया जाता है। गाहे-बगाहे शर्मनाक टिप्पणियां की जाती रही हैं। यदि 21वीं सदी के खुले समाज में हम महिलाओं के प्रति संकीर्णता की दृष्टि से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कि ये वे लोग हैं जिन्हें जनता अपना नेता मानती है और लाखों लोग उन्हें चुनकर जनप्रतिनिधि संस्थाओं में कानून बनाने व व्यवस्था चलाने भेजते हैं। यहां उल्लेखनीय है कि कोलकता में कानून की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है और कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं। निस्संदेह, इसमें दो राय नहीं कि मामले में कानून अपना काम करेगा, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हो जाना चाहिए। इस मामले में टीएमसी नेताओं की टिप्पणियां निस्संदेह निंदनीय हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जानी चाहिए। ममता बनर्जी के सामने एक और चुनौती है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार- हत्याकांड और उसके बाद देश भर में उपजा आक्रोश अभी भी यादों में ताजा है। निःसंदेह, केवल टिप्पणियों से पार्टी को अलग कर देना ही पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक जीवन में जीवन-मृत्यों के खिलाफ जाने वाले लोगों के लिये परिणाम तय होने चाहिए। अन्यथा समाज में ये संदेश जाएगा कि ऐसे कृत्सित प्रयासों के खिलाफ कोई ढंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है। यह भी कि यह एक स्वीकार्य व्यवहार है। यह तर्क से परे है कि किसी पीड़िता को पूर्ण भौतिक व मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना एक आवश्यक कर्तव्य के रूप में निहित क्यों नहीं, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में क्यों न हो। किसी अपराध की रोकथाम अच्छे शासन का एक उपाय है, लेकिन जब कोई अपराध होता है तो प्रभावी प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

विनोद शर्मा, संपादक

अवैध झुगगियों पर चले बुलडोजर से सुलगते सवालों के बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली दंगल में फिर कूदे

कमलेश पांडे

श की राजधानी और दिलवालों के शहर दिल्ली की अवैध झुगगियों पर चले बुलडोजर से उपजते सवालों के बीच प्रमुख विपक्षी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अपने सुलगते आरोपों के साथ कूद पड़े हैं। इससे सत्ताधारी भाजपा की सियासी मुश्किलें बढ़नी स्वाभाविक हैं, जिससे बचने के लिए उसके नेता दलील दे रहे हैं कि कोर्ट के आदेशों के दृष्टिगत यह कार्रवाई चल रही है। लिहाजा इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है। जबकि दिल्ली के दंगल में कूदे अरविंद केजरीवाल अपने पुराने बयानों का हवाला देते हुए याद दिला रहे हैं कि चुनाव से पहले ही उन्होंने झुगगियों पर होने वाली संभावित कार्रवाई के बारे में लोगों को आगाह कर दिया हूं और अब उनका साथ मिला तो दिल्ली सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई उनकी पार्टी लड़ेगी। इसलिए चर्चा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से यहां के सियासी दंगल में कूद पड़े हैं। प्रायः उसी अंदाज में, जैसा कि वो चुनाव से पहले दिखाया करते थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्हें खुद ही मैदान में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह आदि के रहते हुए भी उन्हें किसी सेनानायक की तरह खुद ही सियासी मैदान में उतरना पड़ा। जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद वो पंजाब का रुख कर चुके थे। वहीं, पंजाब व गुजरात विधानसभा उपचुनाव की जीत ने भी उन्हें उत्साहित किया है। बताया जाता है कि भारतीय राजनीति में किसी भी चतुर नेता को सियासी भौत नहीं होती है, बल्कि ब्रेक के बाद उसके फिर से उभरने के चांसेज बने रहते



हैं। बशर्ते कि उसे मुद्दे की समझ हो और जनसंघर्ष की ललक। ये दोनों चीजें केजरीवाल में कूट कूट कर भरी हैं। यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के हारने के कई महीनों बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पूरी राै में दिखे और दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पर फिर उसी तरह से अटैक किया, जैसे वो पहले किया करते थे। इसलिए लोगों के जेहन में यह सवाल कुरेद रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल को दिल्ली के मैदान पर उतरना पड़ा, जबकि दिल्ली में शक्तिस्त के बाद उन्होंने पंजाब में डेरा डाल दिया था। इस बीच कुछ घटनाएं भी हुईं, लेकिन उनके कोर वोटर्स रहे हैं। यही वजह है कि जब उनके कोर वोटर्स के अवैध झुगगियों पर बुलडोजर चला तो अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी टीम के साथ पुनः दिल्ली दाखिल हो लिए और यहां के सियासी दंगल में जोरदार पलटवार

के अंदाज में उतर गए। अपनी सोची समझी रणनीति के मुताबिक वो पहले दिल्ली सरकार, उसके बाद केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने झुगी वासियों को याद दिलाते हुए कहा कि, 'चुनाव से पहले मैंने दिल्ली के गरीबों और झुगीवालों के लिए वीडियो जारी करके कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो यह एक साल में ही झुगगियां तोड़ देंगे। आज वही हो रहा है। ये सारी झुगगियां तोड़ने का इरादा लेकर आए हैं।' इससे स्पष्ट है कि केजरीवाल का मकसद साफ है कि अब दिल्ली में दो-दो हाथ करने हेतु वो फिर से उतर गए हैं। ऐसे में सवाल फिर वही हुआ। समझा जाता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने यहां पर वो कार्ड चल दिया जो केजरीवाल के लिए मुसीबत बन सकता था। क्योंकि अगर ये इस वक्त नहीं बोलते, तो यहां की झुगगियों का एक बड़ा धाँ आने से छूट जाता। इसलिए केजरीवाल ने कहा भी

है कि, दिल्ली की झुगगियों में 40 लाख लोग रहते हैं, यदि ये इकट्ठे हो गए तो किसी की आकांत नहीं है जो आपको झुगी तोड़ने आ जाए। राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि यह सारा खेल इन 40 लाख लोगों यानी वोटर्स का है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल पुनः अपना सियासी मैदान पाने और बचाने, दोनों के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत पुनः मैदान में कूदे हैं। इस प्रकार यदि विधानसभा चुनावों के आंकड़े देखें तो 2015 में आम आदमी पार्टी यानी आप को स्लम वोट में लगभग 66प्रतिशत मिला था। वहीं, सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक, 2020 में आम आदमी पार्टी को 61प्रतिशत वोट यहां मिले। लेकिन 2025 में यह आंकड़ा बदलता दिखा। सियासी कोढ़ में खान यह कि सबसे ज्यादा स्लम वाली 10 सीटों में 7 बीजेपी को मिल गई, जो आपके हार की वजह बनी। लेकिन बीजेपी ने उससे जो गद्दारी की है, उसका सियासी मजा तो वे तब खाएंगे, जब पुनः यहां पर कोई चुनाव होगा। बताते चलें कि दिल्ली में 675 झुगी झोपड़ियां हैं, जहां लगभग तीन लाख परिवार रहते हैं। ये कॉलोनियां यहां की कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 62 विधानसभा क्षेत्रों में फैली हुई हैं। खास बात यह कि इन विधानसभा क्षेत्रों में तकरीबन 40 फीसदी वोटर झुगी झोपड़ियों वाले हैं, जो किसी भी चुनाव में जीत हार तय करने की र्थ्यति में होते हैं। कुछ यही वजह है कि केजरीवाल समझते हैं कि अगर इन्हें छोड़ दिया तो दिल्ली का चुनाव आगे जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इनमें से बहुत सारे वोटर्स केजरीवाल के कोर वोटर्स रहे हैं। आप की फी बिजली-पानी, बस यात्रा, मोहल्ल क्लीनिंग जैसी सुविधाएं, इन लोगों को लुभाती रही हैं और केजरीवाल सरकार के ये बड़े लाभाभी रहे हैं।